

दादरा नगर हवेली में 21 से 23 अप्रैल तक और 23 मई को ड्राई डे : जिला मजिस्ट्रेट कन्नन गोपीनाथन

■ भारतीय एवं विदेशी शराब, बियर तथा ताड़ी की बिक्री एवं सेवाएं रहेगी बंद

सिलवासा, 11 अप्रैल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में लोकसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में 21 से 23 अप्रैल तक और 23 मई को दानह में ड्राई डे रहेगा। इस बावत दानह के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर कन्नन गोपीनाथन ने अधिसूचना जारी की है। चुनाव आयोग के निर्देश और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के प्रावधान पर यह आदेश जारी किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 सी इस प्रकार है। मतदान के दिन लिकर का विक्रय न किया जाना, न दिया जाना और न वितरण किया जाना, मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये

मतदान समाप्त होने के लिये नियम समय के साथ समाप्त होनेवाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्परिटयुक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दो-दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के



लिये सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्परिटयुक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं वे सजा के पात्र होंगे। अतः संघ प्रदेश दानह में 23 अप्रैल को चुनाव और 23 मई को मतदान गिनती के दिन शांति का माहौल बनाये रखने के लिये संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 21 से 23 अप्रैल तक और 23 मई को ड्राई डे रहेगा।

चुनाव पर्यवेक्षक जी. एच. खान ने दानह के दूर-दराज इलाकों के मतदान केन्द्रों पर जाकर चुनाव तैयारियों का लिया जायजा

सिलवासा 11 अप्रैल। दादरा एवं नगर हवेली की लोकसभा सीट के लिए 23 अप्रैल 2019 को मतदान का दिन है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली को संवेदनशील प्रदेश माना गया है। इसी के चलते भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से दादरा एवं नगर हवेली के लिए नियुक्त जनरल चुनाव पर्यवेक्षक जी. एच. खान (आईएएस) पहुंच चुके हैं। चुनाव पर्यवेक्षक ने पिछले दो दिनों में सबसे पहले दानह के दूर-दराज, दुर्गम एवं पिछड़े इलाके जैसे खानवेल के कई पटेलाद, दादरा और डोकमरडी पटेलाद जैसे पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कई पीठासीन अधिकारियों से चुनाव संबंधी की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। विगत रिकार्ड के आधार पर प्रशासन द्वारा संवेदनशील मतदान केन्द्रों की

व्यवस्था का जायजा लिया। मतदान के दौरान अधिक मतदाताओं की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए आने और जाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान केन्द्रों के निकट शौचालय की व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं, इसका भी उन्होंने जायजा लिया। चुनाव पर्यवेक्षक ने राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि एवं उम्मीदवारों के एजेंटों के साथ बैठककर चुनावी आचार संहिता समेत अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही कई जगह उन्होंने मतदाताओं से भी बातचीत की ताकि मतदाताओं को ईवीएम-वीवीपैट मशीन की जानकारी मिली या नहीं। हाल में चुनाव को लेकर पुलिस विभाग के साथ एसएसटी-एफएसटी टीम सतर्क है। आने-जाने वाले सभी वाहनों की जांच मुस्तैदी के साथ होनी



चाहिए। चुनाव पर्यवेक्षक ने नोडल अधिकारियों एवं सेक्टर अधिकारियों समेत चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक वाहन के पंजीकरण नंबर की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और उसमें सवार सभी लोगों की वीडियो भी ली जाए। अगर कोई व्यक्ति शराब ले जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि उसके पास आवश्यक परमिट है या नहीं। इसके अतिरिक्त नगद राशि और (समाचार का शेष पेज 2 पर)



Solo loans drive growth in credit to MSMEs

Output Fails To Increase In Same Scale

Mayur.Shetty
@timesgroup.com

Mumbai: Micro loans availed by borrowers in their individual capacity for business have been the fastest growing segment in commercial credit. According to data compiled by Trans-Union Cibil and Sidbi, micro loans to individuals have grown at 19.2% year-on-year as on December 2018 as compared to 14.4% growth in overall bank credit. There is an increasing number of small businessmen borrowing in individual capacity as access to credit improves.

According to the report, total commercial sector loans stood at Rs 62.3 lakh crore with micro, small and medium enterprises (MSMEs) accounting for Rs 14.8 lakh crore or 23.7% of loans. Within MSME, the micro segment comprising loans of below Rs 1 crore is the fastest growing and stands at Rs 4.5 lakh crore as on December 2018.

This segment has grown at a compounded annual growth rate (CAGR) of 26.1% over the last five years as compared to a 15.7% CAGR in

growth to the MSME sector,

“The comparatively higher rate of business lending to individuals has translated into a major shift in the composition of the MSME lending in favour of individuals,” the report said.

Loans to individuals for business are now 41.3% of MSME lending as against 31% five years ago

However, on the flip side, there are indicators that loans in this sector are coming under stress. NPAs in the individual business loan segment are rising to 8% from below 7% a year ago even as loans to entities in MSME are dropping to below double digits after two years.

Loans to individuals for business are now 41.3% of MSME lending as against 31% five years ago. Small entrepreneurs are raising money for business using facilities such as loans against property, gold loans, loans against shares, loans to professionals, commercial vehi-

cle loans and construction equipment loans.

According to the TU Cibil-Sidbi report, 80% of loans against property and 60% of gold loans are availed for financing business. One reason for this is that credit accessibility has improved significantly. “New-to-credit (first-time) borrowers entering the formal credit sector have accelerated from 2.7 lakh in six months in first half of FY16 to around 3 lakh in first half of FY17 and further to 5.2 lakh in first half of FY18,” the report said. This appears to have been facilitated by the growing share of finance companies in MSME credit.

While this bodes well for financial inclusion, there is a matter of concern. The higher credit is not increasing output in the same scale, which is resulting in the ratio of MSME credit to MSME gross value-added rising from 32.3% in December 2013 to 47.6% in December 18. “Growth of this magnitude needs to be monitored carefully as rapid acceleration in debt build-up is a harbinger of stress in the system,” the report said.